राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
वर्ष 14,अंक 356, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

मिशन शक्ति 5.0: में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानून व योजनाओं की दी गई जानकारी..03

P M O में शिकायत के बाद बड़ा एक्शनः शिक्षा मंत्रालय सख्त, यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जांच के आदेश ..04

जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट... बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) द्वारा मंजूर की जाएगी, उन्हें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है. समावेशन या अपवर्जन के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए।

जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट

राज्य में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को है. दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले फेज की वोटिंग में राज्य के 152 चुनाव क्षेत्रों में जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए हैं. 21 अप्रैल तक वोट देने की इजाजत दी गई है, उन्हें वोट देने की इजाजत दी जाएगी. दूसरे फेज के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल है. अगर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को मंजूरी देता है तो वे लोग वोट दे पाएंगे. हालांकि, जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिये जाते हैं. वे वोट नहीं पाएंगे. जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दी जाएगी. उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी. उस सूची के आधार पर मतदाता मतदान कर पाएंगे. चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन कमीशन ने वोटर लिस्ट को 'फ्रीज' कर दिया है. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

SC ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का किया प्रयोग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल वोटिंग से दो दिन पहले तक विचाराधीन वोटरों के एप्लीकेशन के निपटारे के बाद लिस्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा. हालांकि, विचाराधीन वोटरों के एप्लीकेशन का निपटारा ट्रिब्यूनल को ही करना होगा. सिर्फ वहां अप्लाई करना काफी नहीं होगा. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे. 28 फरवरी को आई पहली सूची में ही करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नामों को विचारणाधीन श्रेणी में रखा गया था. इनमें से 27 लाख 16 हजार 393 लोग अयोग्य पाए गए, जबकि 32 लाख 68 हजार 119 को पात्र मानकर सूची में बहाल किया गया है. मौजूदा समय में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 6,77,20,728 रह गई है. सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी कहा कि 16 लाख अपीलें लंबित हैं. कृपया उनका निपटारा किया जाए. जस्टिस बागची ने कहा कि हाईकोर्ट सीजे ने हमें रिपोर्ट किया है कि अपीलें 34,35,000 के करीब हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ममता ने किया स्वागत

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की. उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी. उन्होंने पार्टी वर्कर्स को अलग से इंस्ट्रक्शन भी दिए. ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में SIR केस फाइल किया था. इसलिए इस फैसले के बाद उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है. ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए नॉर्थ बंगाल में हैं. उन्हें कूचबिहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर मिली. कूचबिहार में हेलीपैड पर उतरते ही ममता बनर्जी ने कहा, 'सभी को बधाई. दिनहाटा से हेलीकॉप्टर में बैठते ही मुझे खुशखबरी मिली. मैं शुरू से कह रही थी, सभी लोग सब्र रखें. मैं बहुत खुश हूं. ज्यूडिशियरी पर गर्व है. मैंने केस फाइल किया. इसलिए आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है।

ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए ये निर्देश

ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स को खास इंस्ट्रक्शन भी दिए. उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम खत्म होने के बाद पार्टी वर्कर्स को घर-घर जाकर वोटर स्लिप बांटनी होगी. ममता बनर्जी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पहले चरण के लिए वोटरों की अतिरिक्त लिस्ट चुनाव से दो दिन पहले 21 तारीख को जारी की जाएगी. जब मुझे यह मिल जाएगी, तो मैं सभी बूथ कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहूंगी कि वे वोटर स्लिप तैयार करें और उसी रात तक उनके घरों तक पहुंचा दें. ताकि जिनके नाम छूट गए हैं, वे वोट दे सकें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अतिरिक्त लिस्ट भी 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग से दो दिन पहले जारी की जाएगी।

भयंकर था वो मंजर... लखनऊ अग्निकांड में 300 से अधिक परिवार बेघर, पिता ने राख खोदकर निकाला बच्ची का शव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। विकासनगर क्षेत्र में बुधवार शाम लगी भीषण आग ने सैकड़ों जिंदगियां उजाड़ दीं। इस दर्दनाक हादसे में 300 से अधिक परिवार बेघर हो गए, जबकि बाराबंकी निवासी एक परिवार की दो मासूम बेटियां जिंदा जल गईं। गुरुवार सुबह जब धुआं थमा तो घटनास्थल पर सिर्फ राख, जली गृहस्थी और बिलखते लोग नजर आए। रिंग रोड स्थित अवैध झुग्गी-झोपड़ियों में बुधवार शाम आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सैकड़ों झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिसमें 300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। आग के दौरान 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने से हालात और भयावह हो गए।

करीब दस किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में सबसे मार्मिक तस्वीर उस पिता की रही, जिसने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया।

बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र के काशीपुरवा निवासी सतीश ने बताया कि आग लगने के वक्त उनकी दो वर्षीय बेटी श्रुति उर्फ स्वाति और दो माह की आयुषी झोपड़ी में सो रही थीं। आग तेजी से फैलने लगी तो परिवार के लोग जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन दोनों बेटियों को नहीं निकाल सके।

गुरुवार सुबह जब मलबे की तलाशी ली गई तो दोनों बच्चियों के शव मिले। बेटियों के शव देखते ही सतीश बेसुध हो गए और बिलखते हुए बोले गृहस्थी के साथ मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा।

गाजीपुर सर्किल के एसीपी ए. विक्रम सिंह के मुताबिक, मलबे से बरामद दोनों शव सतीश की बेटियों के हैं। बताया कि मामले की जांच चल रही है। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ और एनजीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं।

पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों को दफनाया

पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव मिलने के बाद जल्दी ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। करीब 11 बजे दोनों के पोस्टमार्टम हुए और फिर पुलिस ने शव को सिपुर्द कर दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सतीश ने दोनों बच्चियों के शव को दफनाया और वह परिवार के साथ बाराबंकी गांव चले गए। इस दौरान वह दोबारा उस जगह भी नहीं गया जहां झुग्गी झोपड़ी बनी थी।

पार्क में लेटे रहे कई परिवार, नहीं रूके किसी के आंसू

प्रशासन ने कुछ परिवारों को रात में ही रैन बसेरों में ठहराया, जबकि कई लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

अधिकारी बेघर हुए परिवारों की सूची तैयार कर रहे हैं, हालांकि मुआवजे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां मौके पर भेजी गई और लगातार राहत कार्य जारी है।

संक्षिप्त ख़बरें

टेट्रा पैक में शराब बेचने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार

यूपी की शराब नीति के तहत टेट्रा पैक में शराब बेचने के मामले में याचिका दायर की गई , जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता को संबंधित ऑथोरिटी को ज्ञापन देने को कहा. मीनाक्षी तिवारी की तरफ ये जनहित याचिका दायर की गई थी. आज याचिककर्ता की वकील ने कहा कि मेरी बेटी अहमदाबाद में है. उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वहां कोई समस्या नहीं है. लेकिन, उत्तर प्रदेश में बच्चे इन टेट्रा पैक को कक्षाओं में ले जाते हैं. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि नीति का अध्ययन करने पर हमें उसमें टेट्रा पैक में शराब बेचने की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं मिली. हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से फरवरी 2025 में शराब के ऐसे छोटे पैकेटों की अनुमति देने का एक प्रशासनिक फैसला गया था. ये नीतिगत फैसला रिकॉर्ड में है, इसलिए कोर्ट के लिए कोई राय देना उचित नहीं है. चूंकि याचिकाकर्ता ने टेट्रा पैक में शराब की उपलब्धता का आरोप लगाया है।

इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं

कोर्ट ने कहा है कि इसका शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसलिए हम याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ करते हैं कि याचिकाकर्ता इस याचिका की एक कॉपी अधिकारियों को ज्ञापन के रूप में दे सकता है, जो बदले में इस अनुरोध पर विचार कर सकते हैं. अपने आदेश में बेंच ने यह दर्ज किया कि संबंधित नीति दस्तावेज की अनुपस्थिति में इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. इसके बावजूद, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि वह इस मामले को उचित प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उठा सकता है. पिछले साल, एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने टेट्रापैक में शराब की बिक्री पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि इससे छात्रों के लिए स्कूलों में शराब छिपाकर ले जाना आसान हो जाएगा।

कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत, वाहन की टक्कर से हुआ हादसा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। शिवराजपुर में गुरूवार की सुबह हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार बिठूर थाना क्षेत्र के दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए है। पुलिस बाइक में किसी भारी वाहन के टक्कर मार देने से दुर्घटना होने की बात कह रही है। बिठूर के बाकरगंज निवासी 45 वर्षीय विनोद निषाद पुत्र स्व मोहनलाल बाइक से 10 साल की बेटी दीक्षा व रिश्तेदार के बेटे पियूष के साथ किसी काम से बिल्हौर गए हुए थे।

गुरुवार को वह सुबह छह बजे बाइक से परिवार के 54 वर्षीय रामनारायण पुत्र कुंजीलाल निषाद और बच्चों के साथ बिठूर लौट रहे थे। शिवराजपुर दुबियाना गांव के पास बाइक में किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विनोद और रामनारायण व दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाइक सवारों ने नहीं लगाया था हेलमेट

बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाएं थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर हाईवे की एंबुलेंस से सभी को सीएचसी भेजा। जहां विनोद और रामनारायण ने उपचार से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों बच्चों को मंधना के एक निजी अस्पताल में भेजा है। थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि हादसे का सही कारण पता नहीं चल सका है। किसी वाहन द्वारा बाइक में टक्कर मार देने की बात सामने आ रही है। एक बाइक पर चार लोग सवार थे।

समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग व सुविधाओं से बना सुरक्षा का बेहतर माहौलः मुख्यमंत्री योगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोरखपुर- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ। योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वकर्शाप बनाई गई है। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। पर, हम उसका एक ही पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। पहले की सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। बीते 9 वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3 हजार से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है।

योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी

हो, पुलिस लाइन हो या पीएसी वाहिनी, कहीं भी पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी आवासीय सुविधा और अच्छे बैरक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहकर जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करता था। कई बार शिकायत आती थी कि पुलिस वाले ने घर पर कब्जा कर लिया है। वह कब्जा नहीं करता था। होता यह था कि उसके बच्चे की परीक्षा है और उसी समय मकान मालिक घर खाली करने को कह देता। इस पर वह झल्ला कर कहता, घर नहीं खाली करेंगे। आज ये सारी शिकायतें समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने हर पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस थाने का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे। अन्य सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हो पाती थीं। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो उसे रखने की व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे मौकों पर पुलिस असहाय दिखती थी। कई बार अपराधी भाग भी जाता था। लेकिन, पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता, क्योंकि उसे थाने में ही रोककर रखने की सुविधाएं दी गई हैं। अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय, हर थाने में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे। जो थाने की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, उसका काम तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता दिखाई देगा। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन, एडीजी सुरक्षा तरुण गाबा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

जालंधर और गुरुग्राम में लवली ग्रुप के 10 ठिकानों पर ED की रेड, 24 घंटे तक चली छापामारी; दस्तावेज बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

जालंधर। लवली ग्रुप के संस्थानों पर ईडी की रेड वीरवार सुबह करीब पांच बजे समाप्त हुई। ग्रुप के गुरुग्राम और जालंधर सहित दस जगहों पर ईडी ने जांच की थी। लवली ग्रुप के गुरुग्राम स्थित यूनियन कालेज ऑफ बिजनेस एंड मास्टर्स और टीईटीआर कॉलेज आफ बिजनेस कारण ईडी की जांच जालंधर तक पहुंची। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर व राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल उनके भाई रमेश मित्तल और नरेश मित्तल के घर कैंट, लवली स्वीट्स, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जांच के बाद ईडी की टीम कई दस्तावेज और घर व कार्यालयों से कई इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ ले गई है।

परिवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार सुबह लवली ग्रुप के संस्थानों पर दस जगह रेड की थी। जालंधर कैंट स्थित अशोक मित्तल के दोनों निवास, लवली स्वीट्स, लवलीी आटो के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई जिसका नेतृत्व दिल्ली की टीम कर रही थी। जालंधर की ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह करीब पांच बजे रेड की जो वीरवार सुबह पांच बजे खत्म हुई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। ईडी फिलहाल इसे फारेन एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत जांच की बात की है। ईडी ने लवली ग्रुप के गुरुग्राम और जालंधर सहित दस जगह पर जांच करते हुए ग्रुप के विदेशों से लेनदेन का रिकार्ड खंगाला है। ईडी लवली यूनिवर्सिटी और कालेज से जुड़े दस्तावेज ले गई है। सूत्रों की माने तो एससी छात्रों को स्कालरशिप देने में यूनिवर्सिटी और कालेज में अनियमितताएं पाई गई है। जांच में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल उनके भाई रमेश मित्तल, नरेश मित्तल और बिजनेस में सक्रिय अन्य पारिवारिक सदस्यों के दस्तावेज ईडी ने जब्त किए है।

मित्तल परिवार के लिए आप नेता सक्रिय

लवली ग्रुप पर ईडी की रेड के बाद जालंधर के कई आम आदमी पार्टी के नेता उनके पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने इसे रंजिश के तहत की गई कार्रवाई बताया। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा की पंजाब में चुनावी तैयारी बताया था।राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा देने के बाद आप ने इसे राजनीतिक रंजिश की कार्रवाई पर मोहर कहा है।

धोखे से मतांतरण राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, TCS नासिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। नासिक में बहुराष्ट्रीय कंपनी टीसीएस में मतांतरण एवं यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें धोखाधड़ी से होने वाले मतांतरण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका टीसीएस के नासिक कार्यालय में आठ महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न व जबरन मतांतरण के आरोपों की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि धोखे से मतांतरण न सिर्फ संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि भाईचारे, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को मतांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

धोखाधड़ी से मतांतरण रोकने की मांग

साथ ही केंद्र और राज्यों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और यह घोषित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है कि धोखे से मतांतरण पर सजा एक के बाद एक चलेंगी, न कि साथ-साथ। याचिका में कहा गया है कि 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' में धोखाधड़ी, बल, जबरदस्ती या छल से दूसरों का मतांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है।

अनुच्छेद-25 सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन रहते हुए अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उपाध्याय ने यह याचिका अपनी एक लंबित याचिका के सिलसिले में दायर की है, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्यों को धोखे से मतांतरणों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है।

मुस्लिम पर्सनल ला के विरुद्ध याचिका पर केंद्र को नोटिस

मुस्लिम पर्सनल ला (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के कुछ प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से जवाब मांगा। इस चुनौती का आधार यह है कि ये प्रविधान कथित तौर पर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर संज्ञान लिया।

वह याचिकाकर्ताओं पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की ओर से पेश हुए थे। याचिका में कहा गया है कि शरीयत के मौजूदा विरासत नियम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। इन नियमों के तहत अक्सर महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों को मिलने वाले हिस्से का केवल आधा या उससे भी कम हिस्सा दिया जाता है।

जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से हिला कॉर्पोरेट तंत्र

[सिस्टम की परतें खुलीं: शोषण के साथ आस्था पर दबाव के दावे]

[धर्म और अधिकारों के बीच दबाव की दीवार — आईटी सेक्टर का काला सच]

कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमगाहट, कांच की ऊँची इमारतों का मोहक आभास और 'प्रोफेशनलिज़्म' के बड़े-बड़े दावे—यदि इनके भीतर भय, शोषण और दबाव का अंधकार पलता हो, तो यह किसी एक कंपनी की चूक नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी असफलता का संकेत है। अप्रैल 2026 में नासिक स्थित एक आईटी इकाई (टीसीएस) से सामने आया प्रकरण इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहाँ महिला कर्मियों के सपनों को सुनियोजित ढंग से रौंद दिया गया। रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा लेकर आई इन महिलाओं को अपने ही कार्यस्थल पर ऐसे असहनीय दबावों का सामना करना पड़ा, जो किसी भी सभ्य समाज के मूल्यों के सर्वथा विपरीत हैं।

यह मामला केवल यौन शोषण के आरोपों तक सीमित नहीं है; इसके भीतर भय, मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक आस्था पर दबाव और अधिकारों के खुले दुरुपयोग की कहीं अधिक गंभीर परतें छिपी हुई हैं। सामने आई शिकायतों के अनुसार, कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने महिला कर्मियों पर अनुचित प्रस्तावों, अश्लील टिप्पणियों और निजी संबंध बनाने के लिए निरंतर दबाव डाला। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें पदोन्नति रोकने, नौकरी समाप्त करने और उनके निजी जीवन को बदनाम करने की धमकियाँ दी गईं। सत्ता और पद के बल पर किया गया यह आचरण केवल अनैतिकता की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से कानूनन दंडनीय अपराध है, जो किसी भी कार्यस्थल की गरिमा, सुरक्षा और विश्वास को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है।

यह प्रकरण और भयावह तब बनता है, जब स्पष्ट होता है कि यह छिटपुट घटनाएँ नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय संगठित तंत्र का परिणाम था। पुलिस जांच और शिकायतों के अनुसार, आठ महिला कर्मचारियों की नौ एफ़आईआर्स में सामने आया कि टीम लीडर्स सहित वरिष्ठों ने 2022 से 2026 तक करीब चार वर्षों तक सुनियोजित ढंग से उन्हें निशाना बनाकर दबाव में रखा। पुलिस ने फरवरी से 40 दिन तक महिला पुलिसकर्मियों के जरिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाकर साक्ष्य जुटाए। आरोप हैं कि निजी तस्वीरें-वीडियो से ब्लैकमेल करना, नमाज पढ़ने और गोमांस खाने को मजबूर करना, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और मानसिक रूप से तोड़ना—ये सब उसी तंत्र के औजार थे। यह स्थिति दिखाती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग संस्थागत रूप ले लेता है, तो पीड़ितों के लिए आवाज उठाना कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पक्ष मानव संसाधन विभाग की भूमिका पर उठते सवाल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के तहत हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और समयबद्ध, निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। इसके बावजूद आरोप हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, ईमेल और लिखित आवेदन दबाए गए, और पीड़ितों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया—यहाँ तक कि एक एचआर असिस्टेंट जनरल मैनेजर को भी अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिस विभाग पर कर्मचारियों की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी होती है, यदि वही निष्क्रिय या सहभागी दिखे, तो यह कानून की अवहेलना के साथ विश्वास का गंभीर हनन भी है।

चार वर्षों तक लगातार उठती शिकायतों के बावजूद कार्रवाई का अभाव यह स्पष्ट करता है कि समस्या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी खामियों में जड़ें जमाए हुए थी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि 24 घंटे के भीतर संज्ञान लिया जाए और 90 दिनों में जांच पूरी हो, परंतु यहाँ इन प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की गई। यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। ऐसे मामलों में देरी न केवल पीड़ित के मानसिक आघात को गहरा करती है, बल्कि आरोपियों के हौसले भी बढ़ाती है।

'जीरो टॉलरेंस' की नीति का हवाला तब खोखला लगता है, जब सवाल उठता है कि वर्षों तक शिकायतें दबने और पीड़ितों की आवाज अनसुनी रहने के दौरान यह लागू क्यों नहीं हुई। टीसीएस द्वारा उच्च प्रबंधन स्तर पर जांच (सीओओ के निर्देशन में) के आदेश और आरोपियों का निलंबन आवश्यक कदम हैं, पर पर्याप्त नहीं—क्योंकि नेसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज़ सीनेट ने श्रम मंत्रालय से पोश कंप्लायंस ऑडिट की मांग की है। जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; उसे उन सभी स्तरों तक तय होना चाहिए जहाँ लापरवाही या मिलीभगत रही हो। कॉर्पोरेट संस्थानों की साख मुनाफे या छवि से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान, पारदर्शिता और विश्वास से बनती है।

यह घटना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र में कार्यस्थल की सुरक्षा पर गहरे और असहज प्रश्न खड़े करती है। क्या आधुनिक दफ्तर वास्तव में सुरक्षित हैं, या केवल बाहर से सजे-धजे और आकर्षक दिखते हैं? क्या महिलाओं और अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ेगा? यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब तक शिकायत तंत्र मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित और अधूरा ही रहेगा। कर्मचारियों के भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी आवाज न दबेगी, न अनसुनी होगी—बल्कि उसे गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें समयबद्ध न्याय अवश्य मिलेगा। अब समय केवल औपचारिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक सुधार का है। इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच होनी चाहिए, दोषियों को कठोर दंड मिले और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के अनुपालन की स्वतंत्र ऑडिट पूरे आईटी क्षेत्र में कराई जाए। साथ ही मानव संसाधन तंत्र को स्पष्ट रूप से जवाबदेह बनाना और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। कार्यस्थल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण होना चाहिए। यदि इस घटना से भी ठोस सबक नहीं लिया गया, तो यह महज़ एक और मामला बनकर रह जाएगा—और यह किसी भी समाज की सबसे बड़ी विफलता होगी।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

बिछुड़ रहे है सब बारी-बारी...

वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसा क्लब है जहां 60+के सदस्य हैं। लगभग 23 साल हो रहे हैं इसके लिए काम करते-करते। इसमें खुशियां हैं, गम है, सदस्य आते हैं, जाते हैं, ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं परन्तु कई सदस्य अपनी यादें अपने अच्छे व्यवहार, प्यार, अपने क्लब के प्रति समर्पण से हमारे दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं और तभी यह समझ आता है कि जीवन एक पहेली की तरह कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। सच में ऐसे सदस्य हमें बहुत याद आते हैं, क्योंकि इनसे ऐसे संबंध बन जाते हैं जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने सभी सदस्यों को कहते हैं कि आप अपनी सेहत को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी और अपने घरवालों की इजाजत और सहमति से आएं। क्योंकि सबको इतनी खुशियां मिलती हैं कि उन्हें अपनी सेहत की भी परवाह नहीं होती। मुझे तो सारे सदस्य बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत सुकून और खुशियां देती है। उनका उत्साह और जोश देखते ही बनता है परन्तु यही हंसते-खेलते, डांस करते हुए ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं तो मन बहुत उदास होता है। यहां तक कि खाना खाने को भी मन नहीं करता।

यही हमारे साथ हुआ। हमारा जीके 2 ब्रांच का बैसाखी का फंक्शन था। सभी सदस्यों में बच्चों जैसा उत्साह था। गिद्दे, भांगड़ा, डांस, कविता भरपूर था। सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत की हुई थी। हमारी बहुत ही प्यारी सदस्य मेरे साथ मिलकर डांस कर रही थी। हमारी 90 वर्षीय प्रभा जी, 80 वर्षीय वीना शर्मा, डॉ. नीलम नाथ और 80 वर्षीय सुमन कुमार भी इतनी खुश थीं कि मेरे पास शब्द नहीं बयान करने को। हमारे मेहता जी का मंच संचालन और ब्रांच हैड अंजू जी और को-हैड मेहता जी, किरण और उनके हसबैंड की मेहनत दिख रही थी।

हमारी प्यारी सुमन कुमार मेरे साथ झूम रही थीं। क्योंकि डांस करने का अर्थ है एक तरह की एक्सरसाइज। हम सभी सुमन कुमार को प्यार से बेबी डॉल कहते हैं। इस उम्र में इतनी सुन्दर उनके शब्द कम होते लेकिन उनकी अपार स्नेह और समझ होती थी। वह जब डांस कर रही थीं (धीरे) तो सभी ने उन्हें कहा कि बस, पर वह बहुत खुश थी। मुझे बाद में पता चला कि वो गिर गई थीं, परन्तु उनको परवाह नहीं थी। यही नहीं वीना शर्मा अपनी छड़ी छोड़कर नाच रही थीं और प्रभा जी बड़े जोश से गाना गा रही थीं।

मुझे 2 दिन बाद पता चला कि उनको तो फैक्चर हुआ था। मैं हैरान थी कि हमारे जैसे लोगों को छोटी से चोट लगने पर बस हो जाती है और वो तो हमारी प्यारी सी डॉल नाच रही थी।

यही नहीं 4 दिन बाद मुझे पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया, वे अस्पताल में हैं। मुझे यह नहीं मालूम था परन्तु दिल में इतना प्यार था कि मैं तो तुरंत स्वाभाविक रूप से उनका हाल पूछने के लिए फोन कर रही थी। मैं सचदेवा जी के पिता की प्रार्थना सभा में माता सुन्दरी गुरुद्वारे जा रही थी। पहले तो उनका और उनके बेटे का फोन नहीं उठा परन्तु जब मैं गुरुद्वारे में थी तो उनके बेटे ऋषि का फोन आया, जो मैं गुरुद्वारे में उठा नहीं सकती थी। फिर मैंने बाहर आकर जैसे ही कार में बैठी उन्हें फोन किया तो उन्होंने बताया कि उनको 3 बार हार्ट अटैक आया और डाक्टर के बारे पूछ रहे थे। जैसे ही मुझे उनकी डिटेल मालूम पड़ी वो इस संसार से विदा ले गई।

आप सब विश्वास नहीं करोगे जो मेरा दिल बैठा जैसे फिर से अपनी मां को खो दिया। फिर मैं अपनी ब्रांच हैड के साथ उनके घर गई, उनके परिवार को मिलकर बहुत ही सुकून मिला। अधिकतर मैं किसी के ईश्वर को प्यारे होने के बाद जाती नहीं। उनके ब्रांच हैड ही जाते हैं। क्योंकि लाखों सदस्य हैं। हर महीने कुछ सदस्य जाते हैं, कुछ आते हैं परन्तु यह मेरी प्यारी बहू सना की रिश्ते में थी और हमारी बहुत प्यारी सदस्य थीं, तो मैं विशेष रूप से गई। वहां जाकर उनके बेटे-बहू और रिश्तेदारों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनकी बहन, भाभी, भाई, पोते-पोती तथा परिवार के सदस्य मौजूद थे। वे इतने कृतज्ञ थे कि हमारी मां आपके क्लब से बहुत खुशियां पाकर गई हैं। उनका प्यारा बेटा ऋषि कुमार उनको हमेशा छोडने आता था। उनकी प्यारी बहू राधिका उनकी इतनी तारीफ कर रही थी जिसे सुनकर मैं धन्य हो रही थी। घर में एक सुकून था, ऐसी मां फिजिकली वहां नहीं थी परन्तु उनके बच्चों और भाई-बहनों में उनकी प्यारी सी झलक थी और मैं सोच रही थी, काश! मैं उनके जीते जी उनके परिवार में आती तो वह कितनी खुश होतीं, परन्तु इतने सदस्यों के घर जाना सम्भव नहीं। क्योंकि सभी बारी-बारी बिछड़ते हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे और एक दिन आएगा मैं भी नहीं रहूंगी। क्योंकि जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि सब विधि हाथ।

नारी: संघर्ष, संभावनाएँ और समाज की असली परीक्षा

भारतीय संस्कृति में नारी को सृष्टि की जननी, शक्ति और संवेदना का स्रोत माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है - 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' - अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। किंतु यह आदर्श वाक्य आज भी व्यवहारिक जीवन में पूर्णतः साकार नहीं हो पाया है। आधुनिकता के इस युग में, जब हम तकनीकी और आर्थिक प्रगति के शिखर को छूने का दावा करते हैं, तब भी नारी अपने मूलभूत अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है। नारी की समस्याएँ बहुआयामी हैं - सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक। इन समस्याओं को केवल सतही दृष्टि से नहीं, बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर समझने की आवश्यकता है। नारी के संघर्ष की सबसे बड़ी वजह समाज की वह मानसिकता है, जो उसे आज भी पुरुष के समकक्ष स्वीकार करने में संकोच करती है। बचपन से ही लड़कियों को मर्यादा, सीमाओं और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि लड़कों को स्वतंत्रता और अधिकारों की शिक्षा दी जाती है। यह भेदभाव केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे-धीरे एक स्थायी सामाजिक संरचना का रूप ले लेता है। परिणामस्वरूप, लड़की अपने ही अस्तित्व को सीमित मानने लगती है। वह अपने सपनों को छोटा कर लेती है, अपनी इच्छाओं को दबा देती है, और कई बार अपनी पहचान तक खो देती है। समाज को यह समझना होगा कि नारी कोई 'कमतर' इकाई नहीं है, बल्कि वह समान अधिकारों और संभावनाओं वाली एक पूर्ण व्यक्तित्व है।

शिक्षा नारी सशक्तिकरण की आधारशिला है। यह केवल अक्षरज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जागरूकता का माध्यम है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी कई लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं।

गरीबी, सामाजिक रूढ़ियाँ, बाल विवाह और सुरक्षा की चिन्ता - ये सभी कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधा बनते हैं। कई परिवार आज भी यह मानते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च करना 'निवेश' नहीं, बल्कि 'व्यर्थ व्यय' है। यह सोच न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी घातक है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को सकारात्मक दिशा देती है। नारी के सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है उसकी आर्थिक निर्भरता। जब तक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएगी। कामकाजी महिलाओं को भी कई बार समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है। इसके अलावा, घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। घरेलू कार्यों को आज भी 'काम' नहीं माना जाता, जबकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और श्रमसाध्य है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज मेंक्ष सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।घरेलू हिंसा एक ऐसी सच्चाई है, जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न का भी रूप लेती है।कई महिलाएँ इस हिंसा को सहन करती रहती हैं - कभी समाज के डर से, कभी बच्चों के भविष्य के कारण, तो कभी अपनी आर्थिक निर्भरता के चलते। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। आज भी देर शाम घर लौटती एक महिला के मन में एक अदृश्य भय साथ चलता है - यह भय केवल अंधेरे का नहीं, बल्कि उस असुरक्षित सामाजिक वातावरण का है, जो उसे हर कदम पर सावधान रहने को मजबूर करता है।जब तक नारी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, तब तक उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास अधूरा रहेगा। सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं - विज्ञान, राजनीति, कला, शिक्षा, व्यवसाय - हर जगह उनकी भागीदारी बढ़ी है। फिर भी कार्यस्थल पर उन्हें कई प्रकार के भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उच्च पदों तक पहुँचने में 'अदृश्य बाधाएँ' (ग्लास सीलिंग), पदोन्नति में असमानता, और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ आज भी मौजूद हैं। कई बार महिलाओं को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही, मातृत्व को कई बार 'कमजोरी' के रूप में देखा जाता है, जबकि यह एक स्वाभाविक और सम्मानजनक अवस्था है। कई महिलाएँ अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष में मानसिक दबाव का सामना करती हैं। यह स्थिति न केवल महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी बाधक है।

आज की नारी एक ऐसे दौर में जी रही है, जहाँ उसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक आदर्श बेटी, बहू, पत्नी और माँ बने, साथ ही एक सफल प्रोफेशनल भी हो। यह दोहरी अपेक्षाएँ कई बार उसे मानसिक तनाव और आत्म-संघर्ष की स्थिति में डाल देती हैं। वह हर भूमिका में 'पूर्णता' पाने की कोशिश में स्वयं को थका देती है। समाज को यह समझना होगा कि नारी को किसी एक भूमिका में सीमित करना अन्याय है। उसे अपनी पहचान स्वयं गढ़ने का अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए—बिना अपराधबोध के, बिना दबाव के। आधुनिक मीडिया ने नारी की छवि को एक विशेष साँचे में ढालने का प्रयास किया है। 'परफेक्ट' शरीर, गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व - इन सबको सफलता और स्वीकार्यता का मानदंड बना दिया गया है। इसका सीधा प्रभाव युवा लड़कियों के आत्मविश्वास पर पड़ता है। वे अपनी तुलना अवास्तविक छवियों से करने लगती हैं और स्वयं को कमतर महसूस करने लगती हैं। यह आवश्यक है कि समाज नारी को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, विचार और संवेदना से पहचाने।

तकनीकी विकास ने जहाँ महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं, वहीं नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। महिलाओं को उनके विचारों, तस्वीरों और अभिव्यक्ति के लिए निशाना बनाया जाता है। यह एक नया प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, जो उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नारी की समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। महिलाएँ अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। आर्थिक सशक्तिकरणः रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नारी कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह हर समस्या का समाधान बनने की क्षमता रखती है। यदि उसे अवसर, सम्मान और समर्थन मिले, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है।नारी को केवल 'संरक्षण' नहीं, बल्कि 'सशक्तिकरण' की आवश्यकता है। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि समानता चाहिए; दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए।

नारी का संघर्ष केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है; यह समाज की चेतना और संवेदना की परीक्षा है। जिस दिन हम नारी को उसके पूर्ण अधिकारों और सम्मान के साथ स्वीकार कर लेंगे, उस दिन समाज सच्चे अर्थों में विकसित कहलाएगा। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे न लगाएँ, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी नीतियों में वास्तविक परिवर्तन लाएँ।क्योंकि अंततःद्वद्वजब नारी सशक्त होगी, तभी समाज सशक्त होगा, और जब समाज सशक्त होगा, तभी राष्ट्र सच्चे अर्थों में प्रगति करेगा।

डॉ. दीप्ति गुप्ता

चुनाव आयोग पर सुप्रीम सवाल

भारत में जन्मे हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। लोकतांत्रिक सरकार के चुनाव के लिए सहभागी प्रक्रिया में भाग लेना राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह मतदाता सूची में हर जायज मतदाता का नाम शामिल करे। निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उन वोटरों को मतदान की इजाजत देने से इंकार कर दिया है, जिनके नाम एसआईआर में काटे गए हैं और उनकी शिकायतें अपीलीय ट्रिब्यूनलों में लम्बित हैं। 11 अप्रैल तक 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की जा चुकी हैं जिनका फैसला आना बाकी है। स्पष्ट है कि चुनावों से 10 दिन पहले इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ऐसे ही आपत्तियां आती रहीं तो चुनाव कैसे होंगे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जायमाल्या बागची ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दाग दिए और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गम्भीर चिंता जता दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ उन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। चुनाव अधिकारियों की ओर से खारिज की गई विवादित अपीलों की सुनवाई के लिए पूर्व जजों के नेतृत्व में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिनमें से एक की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कर रहे हैं। बनाए गए 19 ट्रिब्यूनलों में से अधिकांश ने काम शुरू ही नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने वोटर लिस्ट फ्रीज करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वोट डालने की अनुमति मिल जाती है तो वे विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। जस्टिस बागची ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि अगर जीत का मार्जन लिस्ट से बाहर किए गए मतदाताओं से प्रतिशत से कम हुआ तो, उन्होंने कहा, 'अगर 10 प्रतिशत लोग वोट नहीं करते हैं और जीत का मार्जिन 10 प्रतिशत से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। अगर जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत है और वोट न करने वाले 15 प्रतिशत हैं, तब क्या होगा? हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है।' जस्टिस बागची ने कहा कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों से अलग है और यहां चुनाव आयोग ने एक नई कैटेगरी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी शुरू की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यहां एसआईआर में लागू उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि 2002 के चुनावों में वोट करने वालों को अपने दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नोटिस में भी यह बात लिखी है।

पीठ ने यह भी कहा कि आपत्तियों और दावों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों से 100 प्रतिशत सही फैसलों की उम्मीद कैसे की जा सकती है जबकि तय समय सीमा के अन्दर एक-एक अधिकारी हर दिन 1000 दस्तावेजों की जांच कर रहा है, ऐसे में 70 प्रतिशत सटीकता की भी उत्कृष्ट मान लिया जाए तो भी गलती होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। इसलिए राज्य में एक मजबूत अपीलीय तंत्र की जरूरत है। पीठ ने यह भी कहा कि कहीं न कहीं हम आने वाले चुनाव की धूल और गुस्से में अंधे हो रहे हैं।

देश की शीर्ष अदालत द्वारा निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस और अन्य दल चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। चुनाव आयोग की ?विश्वसनीयता पर संदेह के बादल गहराते जा रहे हैं। चुनावी लोकतंत्र में विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। निष्पक्षता के अभाव में इसका प्रभाव नागरिक भागीदारी, मतदान के प्रतिशत और सामाजिक एकता पर पड़ता है। भारत में चुनावी लोकतंत्र की मजबूती, उसके नागरिकों के निष्पक्षता पर,? विश्वास पर निर्भर करती है। इस विश्वास के संवैधानिक संरक्षक के रूप में चुनाव आयोग को कानूनी अनुपालन से आगे बढ़कर संस्थागत साख को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल समावेश के सिद्धांत के आधार पर अपीलों को सुने। फिलहाल काटे गए मतदाताओं के सामने ट्रिब्यूनल के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना तय है कि यह काम अब चुनाव के बाद ही होगा।

बिहार को मिला नया 'सम्राट'

बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना केवल एक व्यक्ति का सत्ता में आना नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले कई वर्षों से धीरे-धीरे आकार ले रही थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में 2025 के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 202 सीटें मिलीं, जिनमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीटें थीं, जो उसे सबसे बड़ा दल बनाती हैं । यही संख्या अंततः उस दावे की बुनियाद बनी जिसके सहारे भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया। सम्राट चौधरी का उदय अचानक नहीं हुआ। वे 2024 से उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और वित्त, गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे । इससे पहले वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके थे, जो उनके राजनीतिक अनुभव को दर्शाता है। उनका जन्म 1968 में मुंगेर जिले के एक राजनीतिक परिवार में हुआ और उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार सांसद और विधायक रहे । यह पृष्ठभूमि उन्हें सामाजिक आधार और राजनीतिक नेटवर्क दोनों देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे लंबे समय तक भाजपा के मूल कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि बाद में पार्टी में आए और तेजी से ऊपर उठे, जो यह दर्शाता है कि भाजपा ने उन्हें एक रणनीतिक चेहरा के रूप में विकसित किया। नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर बिहार में लगभग दो दशकों तक प्रभावी रहा। उन्होंने 2005 से लेकर 2026 तक अलग अलग अवधियों में राज्य का नेतृत्व किया और इस दौरान शासन की एक विशिष्ट शैली विकसित की। उनकी सरकार 20 नवंबर 2025 को बनी और 14 अप्रैल 2026 तक चली । इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। अब जब वे पद से हटकर राष्ट्रीय स्तर की भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या उनकी बनाई हुई संरचना को नई सरकार उसी तरह आगे बढ़ा पाएगी।

सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे निरंतरता और बदलाव के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि वे राज्य को विकास के नए आयाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे । इसका अर्थ यह है कि वे पूरी तरह नई दिशा देने के बजाय पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाएंगे। बिहार जैसे राज्य में जहां प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे स्थिर हुआ है, वहां अचानक बड़े बदलाव जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए संभावना यही है कि नीति के स्तर पर निरंतरता बनी रहेगी, जबकि कार्यशैली में परिवर्तन दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू जातीय और सामाजिक समीकरण भी है। बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो राज्य की बड़ी आबादी में शामिल है और जिसे राजनीतिक रूप से संगठित करने की कोशिश लंबे समय से होती रही है। भाजपा ने उन्हें आगे करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि वह केवल पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामाजिक आधार का विस्तार करना चाहती है। यह कदम उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत कर राष्ट्रीय राजनीति में भी संतुलन बनाना चाहती है।

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच संबंध भी इस परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया और सम्राट चौधरी को दो बार उपमुख्यमंत्री बनाया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि नेतृत्व परिवर्तन पूरी तरह टकराव का परिणाम नहीं है, बल्कि एक नियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है। यह भी माना जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, जिससे सत्ता का संक्रमण सहज हो सके। यही कारण है कि इस बदलाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिये से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे साझेदारी के नए चरण के रूप में समझना चाहिए। इस परिवर्तन के साथ बिहार की राजनीति में तुलना का आधार भी बदल जाएगा। अब तक राज्य में विकास और शासन की चर्चा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संदर्भ में होती थी। लेकिन अब यह तुलना सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच होगी। यह बदलाव केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी है। अब यह देखा जाएगा कि क्या नई सरकार उसी गति से विकास कर पाती है या उससे आगे निकलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मजबूत आधार मिल जाएगा। विपक्ष की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस बदलाव को जनादेश के खिलाफ बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होगा। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव जनता की इच्छा के बजाय राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन इसे

विकास और स्थिरता के लिए जरूरी कदम के रूप में प्रस्तुत करेगा।

केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व भाजपा के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश इस समन्वय को और मजबूत कर सकता है। यह स्थिति उस दौर की याद दिलाती है जब राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने से नीति निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आई थी। यदि यह तालमेल बना रहता है तो बिहार को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की बड़ी जरूरत है। सम्राट चौधरी के सामने यह अवसर भी है और परीक्षा भी कि वे इन क्षेत्रों में ठोस परिणाम दिखा सकें। यदि वे केवल राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में ही उलझे रहते हैं तो उनकी सरकार पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। दूसरी ओर यदि वे प्रशासनिक दक्षता और विकास के नए मानक स्थापित करते हैं तो वे अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार में यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक संरचना के पुनर्गठन का संकेत है। इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मौजूद हैं। एक ओर नीतीश कुमार की विरासत है, दूसरी ओर भाजपा की नई रणनीति और सम्राट चौधरी का नेतृत्व। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह प्रयोग कितना सफल होता है और क्या यह बिहार की राजनीति को नई दिशा दे पाता है। फिलहाल इतना निश्चित है कि राज्य एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पुरानी विरासत और नई आकांक्षाएं एक साथ चलेंगी।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

स्कूल चलो अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना

रायबरेली: ब्लाक संसाधन केंद्र अमावां में ब्लाक स्तरीय स्कूल चलो अभियान बाइक रैली एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, खंड विकास अधिकारी अमावां संदीप सिंह ने गोष्ठी में उपस्थिति शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा हर अभिभावक को जागरुक करना है इसके लिए पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं,हमने अपने स्तर से भी उनसे अपील की है। कार्यक्रम आयोजक खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा सिंह ने कहा अभिभावकों से सीधे संपर्क कर एवं स्कूल चलो अभियान रैली के माध्यम से विभाग में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताते हुए उन्हें जागरूक कर बच्चों के नामांकन एवं उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति हेतु निरंतर प्रेरित करते रहना होगा तभी हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, गोष्ठी के उपरांत बाइक रैली को मुख्य अतिथि संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा रैली में प्रतिभाग करते हुए अभियान का हिस्सा बने,रैली चकपीरशाह, थारुइयां मोड़,सिधौना,दुसौती मोड होते हुए पुनः बीआरसी पहुंची जहां खंड शिक्षा अधिकारी अमावां के आभार के साथ उसका समापन हुआ। रैली में मुख्य रूप से एआरपी सतीश चौरसिया, हरीशचंद्र पाण्डेय, मानवेंद्र सिंह, अशोक प्रियदर्शी, सुरेश सिंह, बृजेंद्र सिंह, सूर्य प्रकाश, दयाशंकर तिवारी, संजय सिंह, राजेंद्र यादव, माताबदल कश्यप, बृजेश कुमार, घनश्याम, श्रीकांत, वरुणेंद्र, विजयकांत, गणेश वर्मा, कुलदीप, महताब खान, अफरोज अहमद, अमित यादव, विनोद यादव, गणेश कुमार, हेमंत रमन, संदीप गौतम, रामभरत राजभर, संदीप वर्मा, पवन मौर्या, धीरेन्द्र बहादुर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधियों तथा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही।

सीएचसी परिसर में आग लगने से दो एंबुलेंस जलकर राख

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग कर्मचारी आवास के पीछे खड़ी दो निष्प्रयोज्य एंबुलेंस तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों एंबुलेंस जलकर राख हो गई। घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक एंबुलेंस पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस के पास कूड़ा और करकट पड़ा था। इसी में आग लगी और फैल गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमल पटेल ने बताया कि अस्पताल की बाउंड्री वॉल से सटे खेल मैदान में अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। आशंका है कि बीड़ी या सिगरेट फेंकने से आग लगी होंगी।

महिला ने भट्ठा मुनीम पर लगाया पति और मजदूरों कों बंधक बनाने का आरोप

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे शीतलाबख्श मजरे मधुकरपुर गांव की एक महिला ने गाजीपुर के ईट भट्ठा मुनीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मुनीम ने उसके पति समेत कई मजदूरों को बंधक बना लिया है। गांव निवासी रामरती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके पति रनबहादुर ईट भट्ठे पर मिस्त्री का काम करते हैं। वह गांव और आसपास के राजकुमार, करन, राकेश और रिंकू को भी अपने साथ मजदूरी के लिए लेकर गए थे। महिला ने बताया कि भट्ठा मुनीम मजदूरों के साथ मारपीट कर रहा है। उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा है। यह जानकारी पति ने उसे फोन पर दी जिससे वह बेहद परेशान है। रामरती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर पति और अन्य मजदूरों को मुक्त कराने की गुहार लगाई है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1974 अनुक्रमांक 799497 है, जिसका मूल प्रमाण पत्र (सनद) वास्तव में खो गया है श्री कृष्ण चौधरी पुत्र वंश बहादुर चौधरी ग्राम बरपुर नंबर 9 टोला ऊंची तहसील नौगढ़, जनपद -सिद्धार्थनगर

रफ्तार का कहरः अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, बड़ा हादसा टला- मकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने चालक पर लगाए गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। रहीमाबाद थाना क्षेत्र के अनीपुर गांव में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर घर में घुस जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे गांव निवासी महेंद्र उर्फ टीटू के मकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और घर के अंदर रखा सामान पूरी तरह टूटकर बिखर गया। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय घर के अंदर मौजूद लोग बाल-बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक चालक सराफत सरवन, जो कि केसरिपुर का निवासी बताया जा रहा है, रहीमाबाद की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक अनीपुर गांव के पास पहुंचा, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे महेंद्र के घर में जा टकराया। टक्कर के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस घटना में पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मकान के साथ-साथ घर का कीमती सामान भी बुरी तरह

क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को उजागर कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है।

महमूदाबाद में नवजात का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

महमूदाबाद सीतापुर मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नवजात शिशु का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। यह शव फखरुद्दीन अली अहमद डिग्री कॉलेज के पास, डिग्री कॉलेज से लॉ कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित एक आम के बाग में पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नवजात के दोनों पैर और एक हाथ कटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी जानवर, संभवतः कुत्तों द्वारा नोचा गया हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिशु कुछ ही दिन का प्रतीत हो रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह और कस्बा इंचार्ज दीपक राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

मिशन शक्ति 5.0: में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानून व योजनाओं की दी गई जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद, सीतापुर मिशन शक्ति अभियान 5.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत बुधवार को बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, बिलौली बाजार में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 70 बालिकाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया,गोष्ठी के दौरान पुलिस टीम ने छात्राओं को विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों–1090 (वूमेन पावर लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112, 1076, 102, 108, 181 और 1930–की जानकारी दी और इनके उपयोग के बारे में समझाया इसके साथ ही सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे

में विस्तार से बताया गया, ताकि बालिकाएं इनका लाभ उठा सकें,कार्यक्रम में छात्राओं की काउंसलिंग भी की गई, जहां उनकी समस्याएं सुनी गई और समाधान का भरोसा दिलाया गया। साथ ही उन्हें यातायात नियमों के पालन के प्रति भी जागरूक किया गया। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 70 पंपलेट भी वितरित किए गए,इस अवसर पर महिला आरक्षी शालिनी पांडे, कविता शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

पावर हाउस परिसर में विद्युत विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर सीतापुर नगर स्थित पावर हाउस परिसर में विद्युत विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा द्वारा की गई, जिसमें डिवीजन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा ने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्मार्ट मीटर और कार्यकुशलता पर जोर देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता विभाग की प्राथमिकता है। इस दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अधिशासी अभियंता ने संविदा

लाइनमैनों और फील्ड कर्मचारियों को सुरक्षा किट एवं ड्रेस वितरित की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लाइन पर कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस दौरान प्रमुख रूप से लहरपुर उपखंड अधिकारी अंचल मिश्रा, हरगांव उपखंड अधिकारी अब्दुल अजीज, अवर अभियंता अमरेश कुमार वर्मा, राकेश कुमार, विजय प्रकाश, अभिनव शुक्ला, समेत टीजी 2 व लाइनमैन मौजूद रहे।

सीएचसी परिसर में आग लगने से दो एंबुलेंस जलकर राख

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग कर्मचारी आवास के पीछे खड़ी दो निष्प्रयोज्य एंबुलेंस तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों एंबुलेंस जलकर राख हो गई। घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक एंबुलेंस पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस के पास कूड़ा और करकट पड़ा था। इसी में आग लगी और फैल गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमल पटेल ने बताया कि अस्पताल की बाउंड्री वॉल से सटे खेल मैदान में अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। आशंका है कि बीड़ी या सिगरेट फेंकने से आग लगी होंगी।

पहलवान बाबा उमाशंकर ने भूकंप राणा को किया चित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। डा0 भीमराव आंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर महमूदाबाद विकास खण्ड के जगदीशपुर (हाजीपुर) स्थित त्रिमूर्ति धाम के प्रांगण में मंगलवार रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन हाजीपुर प्रधान प्रतिनिधि धर्मेन्द्र कुमार द्वारा किया गया जिसमें देश एवं प्रदेश के नामी पहलवान शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। दंगल का शुभारंभ अध्यक्ष निर्माण समिति जिला पंचायत सीतापुर शिव कुमार गुप्ता एवं जिलाध्यक्ष सेवा भारती सीतापुर महा नारायण वर्मा ने संयुक्त रूप से पहलवानों का हांथ मिलवा कर किया। कार्यक्रम में संजय कुमार वर्मा, रमाशंकर वर्मा, अनिल कुमार यादव,मोहन प्रसाद बारी,नमन कुमार गुप्ता, मुन्ना जादूगर, सुरेश चौहान, दिनेश

कुमार, वीरेंद्र व निहाल खान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इस विराट कुश्ती दंगल में उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब,दिल्ली,नेपाल व अयोध्या के नामी गिरामी युवा पहलवानों ने दांव आजमाये। दंगल में महिला पहलवानों की उपस्थिति ने दर्शकों में जोश भर दिया। दंगल का महा मुकाबला महिला पहलवान चीमा कानपुर व खुशी पहलवान दिल्ली के बीच हुआ जिसमें खुशी ने कड़े मुकाबले में चीमा को पटखनी देकर जीत हासिल की। दंगल का फाइनल मुकाबला राजस्थान के पहलवान भूकंप राणा और अयोध्या हनुमानगढ़ी के मशहूर पहलवान बाबा उमाशंकर के बीच हुआ जिसमें काफी देर तक उठा पटक के बाद बाबा उमाशंकर ने भूकंप राणा को चित कर मुकाबले का खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजकों द्वारा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

हिंद के लाल थे बाबा अम्बेडकर:- पिंकी अरविंद प्रजापति

● जो पढ़ता निज इतिहास नहीं गढ़ पाता इतिहास नहीं:- देवेन्द्र कश्यप निडर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख। कस्बा के डाक बंगला परिसर में डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के शुभ अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी मसूरी के पूर्व प्रशिक्षक और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से दलित साहित्य पर पीएचडी करने वाले डॉ गंगा प्रसाद शर्मा 'गुणशेखर' ने कहा कि अम्बेडकर ने भारत के समग्र उन्नति का आधार तैयार किया जो आज भी प्रासंगिक हैं। कवि देवेन्द्र कश्यप निडर ने पढ़ा जो हित का करता काम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं। जो कर में रखता कलम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं। सारी दुनिया की तारीखे इसकी करती तस्दीक निडर, जो पढ़ता निज इतिहास नहीं गढ़ पाता है इतिहास नहीं। कवयित्री पिंकी अरविंद प्रजापति ने पढ़ा ज्ञान का सिन्धु जब हो गए बन्धुवर।

मान सम्मान पाया सितम झेलकर।
लिख गए संविधान वो सबके लिए
हिन्द के लाल थे बाबा अम्बेडकर।।

पिंकी अरविन्द प्रजापति, रोहित विश्वकर्मा ने मंच संचालन करते हुए पढ़ा सही रहने का ठौर आएगा।

मेरी बगिया में बौर आएगा।
इस तरह जुल्म ना करों यारों
कभी मेरा भी दौर आएगा।

कानपुर के सैनिक व कवि लाल सिंह प्रहरी ने पढ़ा खिलाफ हवाओं में खुदको संभाल रक्खा है। भंवर से भी कश्ती निकाल रक्खा है। वाकिफ हूं हिमालय की ऊंचाईयों से, सिंधु भी मैंने खंगाल रक्खा हूं। कार्यक्रम संयोजक व कवि राम जीवन मिश्रित ने पढ़ख जश्न मुबारक तुम्हे भूखे पेट त्यौहार हमने मनाए हैं, खुशबू मुबारक तुम्हे पसीने से फूल हमने कमाए हैं, कहां आसान थे मेरे रास्ते कांटो पर चलना सीखा, बारिश का तुम इस्तकबाल करते हो बिस्तर हमने खिसकाए

हैं। लखीमपुर पुर के पवन तारा ने पढ़ा ज़मीं पे रहकर आवाज देना, जमीं से तारे पसंद करना। कभी सवालों को न बदलना न इन आवाजों को बंद करना। हमारे पुरखों ने हमसे बोला , हमारे रहबर ने ये कहा है। कभी न सिर को झुकाना अपने हमेशा नारे बुलंद करना। अनिल अनिकेत ने पढ़ा उलटी सीधी जो कोई बकता है। स्वाद अपने किये का चखता है। आप खुद को खुदा नहीं समझो, वक्त सबका हिसाब रखता है। सागर उन्नावी और तरन्नुम नाज ने भी खूबसूरत काव्यपाठ किया। इस मौके पर ओमकार नाथ पुष्कर, अमित गौतम, नन्दलाल, एड. अजय पाल सिंह, बबलू दीक्षित, वीपी हंस, कुसुम सहित हजारों लोग उपस्थित रहे।

शिया पीजी कॉलेज के विधिक सहायता केंद्र का दौलतगंज में शिविर, घर-घर पहुंचकर सुनी समस्याएं

लखनऊ। शिया पीजी कॉलेज, विधि संकाय के विधिक सहायता केंद्र द्वारा बुधवार को दौलतगंज वार्ड स्थित मुगल पैलेस हॉल में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय 'भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था: चुनौतियां एवं समाधान' रहा। इस दौरान क्षेत्र में रैली निकालकर टीम ने घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के सुझाव दिए। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य/इंचार्ज विधि संकाय प्रो. एस. सादिक हुसैन आबिदी ने हरी झंडी दिखाकर की। शिविर में उप निदेशक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने विधिक सहायता केंद्र की स्थापना, उद्देश्य एवं संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी। विधिक सहायता केंद्र के निदेशक डॉ. वहीद आलम ने भारतीय आपराधिक कानून, विशेषकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, थाने और कोर्ट में आने वाली समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हुए समाधान बताए। उप निदेशक डॉ. उग्रसेन ने लोगों से अपील की कि किसी भी विधिक सहायता के लिए केंद्र से संपर्क करें। वहीं डॉ. प्रिया सिंह ने जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग के लिए निशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। शिविर में बड़ी संख्या में विधि के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और जागरूकता अभियान को सफल बनाया।

रामपुर घाट पर धड़ल्ले से शुरू हुआ अवैध बालू का धंधा,बालू माफिया सक्रिय

गोपीगंज। शासन की सख्ती और अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में बालू माफिया पुनः सक्रिय,। अवैध बालू रामपुर गंगा घाट पर इन दिनों नाव के सहारे लाए जाने का सिलसिला खुलेआम शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार, गंगा पार से नावों के जरिए स्थानीय नाविक बालू लाकर घाट पर उतारते हैं, जिसके बाद इसे आसपास के क्षेत्रों में खपाया जाता है। यह पूरा खेल लंबे समय से जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अनजान बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कारोबार में संलिप्त माफिया खनन विभाग और पुलिस को मोटी रकम देकर कार्यवाही से बचते हैं। यही वजह है कि प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि शासन द्वारा अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, इसके बावजूद रामपुर घाट पर इस तरह खुलेआम नियमों की अनदेखी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

शारदा सहायक नहर पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी

बिसवां/सीतापुर बुधवार को शारदा सहायक नहर पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्राम पुरैनी के पास नहर में एक युवक का शव उतराता हुआ देखा गया। मृतक शर्ट और अंडरवियर पहने था। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। काफी प्रयास के बावजूद मृतक की पहचान नहीं हो सकी। प्रभारी निरीक्षक राम राघव सिंह ने बताया कि शव पुराना प्रतीत हो रहा है और अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रोजगार सेवकों ने मानदेय न मिलने के विरोध में किया बड़ा आंदोलन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/ रायबरेली: विकासखंड महराजगंज में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों ने पिछले 11 महीनों से मानदेय न मिलने के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रांतीय आह्वान पर सभी रोजगार सेवक 16 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। इस निर्णय से मनरेगा कार्यों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि, बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय पर एकत्रित होकर रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और खंड विकास

अधिकारी वर्षा सिंह को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, लंबे समय से मानदेय न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। रोजगार सेवकों ने चेतावनी दी कि, यदि शीघ्र ही बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, तो वे प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी मांग करी कि, हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी पर कार्य करने का दबाव न बनाया जाए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह ने आश्वासन दिया कि, रोजगार सेवकों का ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह, शिव मोहन तिवारी, पूनम यादव, शिव शंकर मौर्य, अनुपम पांडेय, अलका वर्मा, छाया रानी, अरुण कुमार, अवधेश कुमार, बड़ी संख्या में रोजगार सेवक मौजूद रहे।

एनएसएस स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर लोगों से किया संवाद

लखनऊ। शिया पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) द्वारा बुधवार को दौलतगंज वार्ड में एक दिवसीय 'कानूनी मामलों में सलाह' शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली निकालकर स्वयंसेवकों ने क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के सुझाव दिए। रैली से पूर्व आयोजित शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉ. वहीद आलम ने वार्ड निवासियों एवं एनएसएस स्वयंसेवकों को भारतीय आपराधिक कानून, विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली, थाने और कोर्ट में आने वाली आम समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके व्यावहारिक समाधान भी बताए। शिविर में एनएसएस के बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया और जागरूकता अभियान को सफल बनाया।

कार्यालय ग्राम पंचायत बघेलखंड विकासखंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

पत्रांक- ग्रा पं / निविदा पत्रांक / 2026-27 दिनांक 17-04-2024

अल्पकालिक निविदा

वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा, पंचम राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग (पंद्रहवाँ वित्त) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मिशन कायाकल्प पंचायत भवन निर्माण / मरम्मत सामुदायिक शौचालय निर्माण/आर आर सी सेंटर निर्माण / मरम्मत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण / मरम्मत एवं अन्य सरकारी कार्य (खड़ंजा, नाली निर्माण सोख्ता गड्ढा निर्माणआदि कार्य), गौशाला प्रबंधन, जो ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाएंगे जैसे ह्यूम पाइप, इंटरलॉकिंग ईट एवं अन्य सामग्री रजिस्टर्ड फर्मध् एजेंसीज से प्रथम श्रेणी ईट, सीधा खड़ंजा ईट, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, बालू सरिया, सीमेंट, टाइल्स, पेंट, शौचालय ईट, लोहे का दरवाजा, इंडिया मार्का हैंड पंप, मरम्मत एवं रिबोर बिजली उपकरण, टीन शेड, भूसा क्रय, तार जाली. ई रिक्शा, सोलर लाइट, पंप ओपेन जिम से संबंधित सामग्री आदि की आपूर्ति ग्राम पंचायत में संचालित गो आश्रय हेतु भूसा, दाना, हरा चारा, चारा मशीन, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग मशीन, डस्टबिन, प्लास्टिक बैंक एवं शाशन द्वारा निर्धारित अन्य कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 17-04-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर 12:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी दिनांक 20-04-2026 को 12:00 बजे खोली जाएगी। सामग्री की मात्रा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार अलग-अलग होगी किसी भी निविदा / कोटेशन का स्वीकृति करने या संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

नीरज कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत बघेलखंड
विकास खंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

नसीम अहमद
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघेलखंड
विकास खंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत बनगाई विकासखंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

पत्रांक- ग्रा पं / निविदा पत्रांक / 2026-27 दिनांक 17-04-2024

अल्पकालिक निविदा

वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा, पंचम राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग (पंद्रहवाँ वित्त) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मिशन कायाकल्प पंचायत भवन निर्माण / मरम्मत सामुदायिक शौचालय निर्माण/आर आर सी सेंटर निर्माण / मरम्मत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण / मरम्मत एवं अन्य सरकारी कार्य (खड़ंजा, नाली निर्माण सोख्ता गड्ढा निर्माणआदि कार्य), गौशाला प्रबंधन, जो ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाएंगे जैसे ह्यूम पाइप, इंटरलॉकिंग ईट एवं अन्य सामग्री रजिस्टर्ड फर्मध् एजेंसीज से प्रथम श्रेणी ईट, सीधा खड़ंजा ईट, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, बालू सरिया, सीमेंट, टाइल्स, पेंट, शौचालय ईट, लोहे का दरवाजा, इंडिया मार्का हैंड पंप, मरम्मत एवं रिबोर बिजली उपकरण, टीन शेड, भूसा क्रय, तार जाली. ई रिक्शा, सोलर लाइट, पंप ओपेन जिम से संबंधित सामग्री आदि की आपूर्ति ग्राम पंचायत में संचालित गो आश्रय हेतु भूसा, दाना, हरा चारा, चारा मशीन, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग मशीन, डस्टबिन, प्लास्टिक बैंक एवं शाशन द्वारा निर्धारित अन्य कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 17-04-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर 01:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी दिनांक 20-04-2026 को 01:00 बजे खोली जाएगी। सामग्री की मात्रा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार अलग-अलग होगी किसी भी निविदा / कोटेशन का स्वीकृति करने या संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

नीरज कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत बनगाई विकासखंड
गैसड़ी जनपद बलरामपुर

राम सिंह यादव
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बनगाई विकासखंड
गैसड़ी जनपद बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत विश्रामपुर विकासखंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

पत्रांक- ग्रा पं / निविदा पत्रांक / 2026-27 दिनांक 17-04-2024

अल्पकालिक निविदा

वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा, पंचम राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग (पंद्रहवाँ वित्त) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मिशन कायाकल्प पंचायत भवन निर्माण / मरम्मत सामुदायिक शौचालय निर्माण/आर आर सी सेंटर निर्माण / मरम्मत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण / मरम्मत एवं अन्य सरकारी कार्य (खड़ंजा, नाली निर्माण सोख्ता गड्ढा निर्माणआदि कार्य), गौशाला प्रबंधन, जो ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाएंगे जैसे ह्यूम पाइप, इंटरलॉकिंग ईट एवं अन्य सामग्री रजिस्टर्ड फर्मध् एजेंसीज से प्रथम श्रेणी ईट, सीधा खड़ंजा ईट, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, बालू सरिया, सीमेंट, टाइल्स, पेंट, शौचालय ईट, लोहे का दरवाजा, इंडिया मार्का हैंड पंप, मरम्मत एवं रिबोर बिजली उपकरण, टीन शेड, भूसा क्रय, तार जाली. ई रिक्शा, सोलर लाइट, पंप ओपेन जिम से संबंधित सामग्री आदि की आपूर्ति ग्राम पंचायत में संचालित गो आश्रय हेतु भूसा, दाना, हरा चारा, चारा मशीन, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग मशीन, डस्टबिन, प्लास्टिक बैंक एवं शाशन द्वारा निर्धारित अन्य कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 17-04-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर 02:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी दिनांक 20-04-2026 को 02:00 बजे खोली जाएगी। सामग्री की मात्रा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार अलग-अलग होगी किसी भी निविदा / कोटेशन का स्वीकृति करने या संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

मनोज कुमार यादव
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विश्रामपुर
विकास खंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

नीरज कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत विश्रामपुर
विकास खंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

संक्षिप्त खबरें

वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव, अब आधार नहीं होगा मान्य आयु प्रमाण

ज्ञानपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना के तहत आवेदकों की आयु की गणना के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य माना जाता था, लेकिन शासन के नए दिशा-निदेशों के अनुसार अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को आयु प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों में जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित नए नियमों का पालन करें और सही दस्तावेज अपलोड करें, ताकि उन्हें पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि गलत या अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आर्टिगा कार से टक्कर मारकर हत्या मामले में गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार, भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ज्ञानपुर। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कमलाकांत दूबे की दुकान का शटर बंद करते समय आर्टिगा कार से टक्कर मारकर हत्या करने की घटना में शामिल गैंगस्टर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देशन में अपराध एवं कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मामले में पहले ही चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, मनीष यादव के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय था, जिसमें मेहीलाल, सुजीत यादव और अंकित यादव उर्फ लवकुश शामिल हैं। यह गिरोह लोगों के साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है। इसी क्रम में 14 अप्रैल 2026 को थाना भदोही पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट (मु0अ0सं0 165/26, धारा ×(1)) से संबंधित वांछित अभियुक्त मेहीलाल (56 वर्ष) निवासी धसकरी, थाना व जिला भदोही को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। भदोही पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मिशन शक्ति फेज-5.0' के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष जागरूकता अभियान

ज्ञानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत जनपद भदोही में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में जिले के सभी थानों द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस टीमों ने गांव, कस्बों, मौहल्लों और शिक्षण संस्थानों में भ्रमण कर चौपाल लगाई। महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के उपाय, गुड टच बैड टच की पहचान और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। छेडख़ानी या किसी भी अपराध की स्थिति में 1090 वीमेन पावर लाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई। साथ ही अन्य जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के सावधानीपूर्वक उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के टिप्स दिए गए। महिलाओं और बालिकाओं को यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया। पुलिस का उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के मंत्र के साथ महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाना है।

ऐसा क्या हो गया था जो ट्रंप ने तुरंत मोदी को फोन लगाया और 40 मिनट तक बातचीत की?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

एक ओर पाकिस्तान की कूटनीति धराशायी हो चुकी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति वैश्विक मंच पर ऐसे गूंज रही है कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही। हालिया घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र भारत बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई ताजा बातचीत बदलती विश्व व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है। करीब चालीस मिनट चली इस बातचीत में जिस तरह द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर चर्चा हुई, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक धुरी बन चुका है। यह वही भारत है जिसे कभी क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज वही भारत वैश्विक फैसलों के केंद्र में बैठा है। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहन विचार विमर्श रहा। होरमुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर देना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा को बचाने का स्पष्ट संदेश है। यह वही मार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा जरूरतें गुजरती हैं। ऐसे में भारत की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि अब वह केवल अपने हितों तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता का जिम्मेदार प्रहरी बन चुका है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह घटनाक्रम कई स्तरों पर भारत के लिए निर्णायक है। अमेरिका के साथ संभावित बड़े समझौते इस दिशा में एक ठोस कदम हैं। यह केवल तेल या गैस की खरीद नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा का ढांचा है। जब कोई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर लेता है, तो वह आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर मजबूत हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग है। अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी का मतलब है कि भारत अब वैश्विक उत्पादन और तकनीकी ढांचे में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह वह क्षेत्र है जहां भविष्य की ताकत तय होती है।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का यह कहना कि आने वाले दिनों में बड़े समझौते अंतिम रूप ले सकते हैं, इस बात का संकेत है कि दोनों देश अब परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यह वही बदलाव है जो भारत की कूटनीति को अलग बनाता है। गोर के मुताबिक, बातचीत के अंत में ट्रंप ने मोदी से कहा, 'मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं।'' उधर, ट्रंप से बातचीत के बाद मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था।

हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की।' उन्होंने लिखा, 'हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला एवं सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। 'देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच अनिश्चितता, समुद्री मार्गों पर खतरा और युद्धविराम की नाजुक स्थिति ने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल रखा है। ऐसे समय में भारत का संतुलित रुख उसे एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

भारत न तो किसी सैन्य गठबंधन में कूद रहा है और न ही निष्क्रिय बैठा है, बल्कि कूटनीतिक संतुलन के साथ अपने हितों और वैश्विक स्थिरता दोनों को साध रहा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच निरंतर संवाद इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल अवसर आधारित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित हैं। यह संबंध अब उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर स्थिरता की दिशा में बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद से यह मोदी और ट्रंप की दूसरी वार्ता थी। इसके अलावा, अगले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत कर सकती है। यह यात्रा कई बड़े फैसलों की भूमिका तैयार करेगी। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी अमेरिका यात्रा पर गये थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है।

दादा देव मंदिर में बैसाखी पर्व पर भव्य आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। महेश मिश्रा पालम गांव स्थित प्रसिद्ध दादा देव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बैसाखी पर्व के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना एवं हवन के साथ हुई, जिसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।मंदिर की स्थापना लगभग 1400 वर्ष पूर्व मानी जाती है और तब से यह आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पालम गांव सहित आसपास के बारह गांवों के श्रद्धालु दादा देव के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।दादा देव समिति के मीडिया प्रभारी रणबीर सिंह सोलंकी ने जानकारी दी कि दादा देव की कृपा से समस्त क्षेत्र में सुख-समृद्धि एवं स्वास्थ्य का वास बना रहता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासी प्रत्येक शुभ कार्य–चाहे वह विवाह हो या कोई व्यावसायिक आरंभ–से पूर्व दादा देव का स्मरण अवश्य करते हैं।समिति के प्रधान ओमवीर सोलंकी ने अपने संबोधन में कहा कि दादा देव सदैव क्षेत्र के संरक्षक के रूप में उपस्थित रहते हैं और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित थे। वर्ष भर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, किंतु बैसाखी एवं शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन का महत्व अधिक होता है। मीडिया प्रभारी रणबीर सिंह सोलंकी ने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनके सहयोग एवं सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर रामचंद्र पहलवान महासचिव सुरेंद्र यादव उपप्रधान भूप सिंह, सतबीर सिंह, हरी सिंह, कोषाध्यक्ष जिले सिंह सहित पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, सांसद रामवीर बिधूड़ी, विधायक कुलदीप सोलंकी, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी, पूर्व विधायक विजय लोचव, विधायक कैलाश गहलोत, विधायक संदीप सहरावत, पूर्व पार्षद पवन शर्मा, पार्षद नरेंद्र गिरसा, सहरावत खाप दिल्ली प्रदेश के उपप्रधान करमवीर सहरावत एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

PMO में शिकायत के बाद बड़ा एक्शनः शिक्षा मंत्रालय सख्त, यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जांच के आदेश

● व्यापारी नेता जितेंद्र चतुर्वेदी की पहल रंग लाई, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म थोपने के मामले में केंद्र ने लिया संज्ञान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। निजी विद्यालयों द्वारा महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और तय दुकानों से खरीद के दबाव के खिलाफ की गई शिकायत पर अब केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश संगठन महामंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जितेंद्र चतुर्वेदी द्वारा दर्ज कराई गई जन शिकायत को उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक एवं समग्र शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

गौरतलब है कि जितेंद्र चतुर्वेदी ने अपने शिकायत पत्र में प्रदेश भर के निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने, तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपने का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि कई स्कूल स्वयं ही किताबों की बिक्री कर रहे हैं या कुछ निश्चित दुकानों से खरीदारी के लिए बाध्य करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि यह केवल उनकी नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों अभिभावकों की आवाज है, जो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस दिशा में सख्त कार्रवाई होती है, तो इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को और बड़े स्तर पर उठाया जाएगा, ताकि निजी विद्यालयों की मनमानी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

सुरियावा-निगोह मार्ग की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान, चौड़ीकरण व मरम्मत की उठी मांग

सुरियांवा। सुरियावा निगोह मार्ग से बेला त्रिमुहानी होते हुए ग्राम अबरना, हरिहरपुर, बिसही, विसापुर, सांडा व पूरे बदल तक जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। हरिहरपुर अस्पताल के पास सहित कई स्थानों पर सड़क धंस गई है और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग 24 घंटे व्यस्त रहता है और आसपास के कई गांवों को जोड़ते हुए सीधे जौनपुर तक संपर्क स्थापित करता है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क संकरी होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, वहीं खराब सड़क के चलते आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में वीरेंद्र प्रताप सिंह, धर्मराज यादव, विनोद कुमार, आशुतोष कुमार व राजकुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण और मरम्मत की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

ईरान के नुक्लेअर प्रोग्राम पर अमेरिका का रुख साफ, उपराष्ट्रपति बोले- 'परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और प्रशासन इस नीति को लागू करवाने के लिए काम कर रहा है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में आयोजित 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' कार्यक्रम में बोलते हुए वैंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप एक व्यापक समझौते की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने एक नीति निर्धारित की है: ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और अभी हम यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास यह युद्धविराम है, जो मुझे लगता है कि छह या सात दिन पुराना है। अभी यह युद्धविराम कायम है और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं, वह कोई छोटा समझौता नहीं करना चाहते। वैंस ने कहा कि अमेरिका ईरान को सामान्य आर्थिक संबंधों का रास्ता दिखा रहा है, बशर्ते वह अपना आचरण बदले।

उन्होंने कहा कि ईरान को उनका प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है और सच कहूँ तो ऐसा प्रस्ताव देने की क्षमता किसी भी राष्ट्रपति के पास नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करने को तैयार हैं, तो हम भी आर्थिक रूप से आपके साथ एक सामान्य देश जैसा व्यवहार करेंगे।

उन्हें कोई छोटा-मोटा समझौता नहीं चाहिए। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान में हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन समझौता अभी तक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि राष्ट्रपति वास्तव में ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार न हों, ईरान आतंकवाद को प्रायोजित न करे, और साथ ही ईरान के लोग समृद्ध और खुशहाल हों और विश्व अर्थव्यवस्था में उस तरह से योगदान दे सकें जैसा उन्होंने मेरे जीवनकाल में कभी नहीं दिया।

वैंस ने आगे कहा कि और यही वो ट्रम्पवादी भव्य समझौता है जिसे राष्ट्रपति ने सामने रखा है। हम बातचीत जारी रखेंगे और इसे साकार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं इसे साकार करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। ये टिप्पणियां तब आई जब ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह ईरान के साथ चल रहे दो सप्ताह के युद्धविराम को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में तनाव को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत के जरिए समझौता करना ही है।

प्रयागराज पावर प्लांट में चार हजार मजदूरों का उग्र प्रदर्शन

● प्रबंधन पर शोषण का आरोप।8 घंटे के स्थान पर 12 ड्यूटी लेने का आरोप। निर्धारित मजदूरी दर न मिलने का आरोप।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बारा प्रयागराज। यमुनानगर के बारा क्षेत्र में स्थित प्रयागराज पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PPGCL) में मंगलवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब 4000 से अधिक मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूरों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे पूरे प्लांट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

12 घंटे की ड्यूटी बनी विवाद की जड़

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आरोप है कि उनसे जबरन 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि उन्हें निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी ही दी जानी चाहिए। मजदूरों ने इसे 'गुलामी जैसी स्थिति' बताते हुए तत्काल बदलाव की मांग की है।

वेतन वृद्धि को लेकर भी नाराजगी

मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें पुराने और बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वर्करों ने स्पष्ट कहा कि अब केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि वेतन वृद्धि को लेकर लिखित समझौता चाहिए। बिना लिखित आश्वासन के वे काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं।

नारों से गूंजा पूरा बारा इलाका

सुबह से ही मजदूरों का जमावड़ा शुरू हो गया था, जो देखते ही देखते 4000 के पार पहुंच गया। 'हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते!' जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन और प्रबंधन अलर्ट

इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी प्रबंधन के साथ-साथ प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। हालांकि अभी तक मजदूरों और प्रबंधन के बीच कोई ठोस वार्ता नहीं हो सकी है।

उत्पादन पर असर की आशंका

लगातार जारी इस हड़ताल से प्लांट के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला, तो बिजली उत्पादन और आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बताया जाता है इस प्लांट में मजदूरों का काफी अरसे से शोषण हो रहा है ।इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर सीज़दूरी नहीं दी जाती।बोनस एल की तो बात दूर रही। 8 घंटे से ऊपर काम करने पर ओवर टाइम देने का नियम है जो निर्धारित दर से दो गुना देना चाहिए लेकिन यहां कुछ भी नहीं दिया जाता। यहां काम करने वाले गरीबों आदिवासी दलितों , और अन्य कमजोर लोगों की गरीबी का फायदा प्रबंधन काफी दिनों से उठा रहा है। न तो इनकी मांग को यहां के विधायक उठाते है न ही समाज सेवी न ही श्रम विभाग न ही पत्रकार। आरोप है कि प्रबंधन ने सबको उपकृत कर के मजदूरों का शोषण करता है।पता चला है इस क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी को यहां के प्रबंधन ने परिसर के अंदर एक सुसज्जित आवास दे रखा है जिससे भय के मारे मजदूर अपनी आवाज न उठा सके।

किसान दिवस आयोजित, योजनाओं की दी गई जानकारी, समस्याओं के समाधान का आश्वासन

ज्ञानपुर। जनपद भदोही के विकास भवन सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं किसानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और विभागीय योजनाओं की जानकारी देना रहा। उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि सभी कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री जरूरी है, अन्यथा लाभ रोका जा सकता है। उन्होंने किसानों से जल्द से जल्द सहज जन सेवा केंद्र, लेखपाल या कृषि विभाग के माध्यम से पंजीकरण कराने की अपील की। कार्यक्रम में सोलर पंप योजना, कृषि यंत्रीकरण और फसल सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला कृषि अधिकारी कु. ईरम ने बताया कि जल्द ही राजकीय बीज भंडार पर ढैंचा का बीज उपलब्ध होगा, जिससे किसान बुवाई कर सकते हैं। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि राम प्रकाश ने बताया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से ओवररेटिंग या टैगिंग की शिकायत मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की। साथ ही नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग पर भी जोर दिया गया। नहर विभाग के सहायक अभियंता ने जानकारी दी कि 26 अप्रैल से नहरों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे तालाब और पोखरों को भरा जा सकेगा। वहीं नलकूप विभाग द्वारा भी गर्मी में जल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। मत्स्य निरीक्षक सुषमावती ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि निजी तालाबों पर अनुदान दिया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से डॉ. गीता ने खुरपका-मुंहपका व गलाघोटू रोगों के टीकाकरण के लिए पशुपालकों को जागरूक किया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता एस.पी. पटेल ने किसानों से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की, अन्यथा कनेक्शन वि'छेद की चेतावनी दी। किसान दिवस के दौरान किसानों ने बिजली, नलकूप और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं भी रखीं। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

8 महीने से बंद स्ट्रीट लाइट, पासी चौराहा अंधेरे में- राहगीर परेशान

सीतामढ़ी। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत इटहरा के पास स्थित पासी चौराहा पिछले लगभग 8 महीनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। यहां जिला पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, जिससे रात होते ही पूरे चौराहे पर घना अंधेरा छा जाता है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों और राहगीरों पर पड़ रहा है, जिन्हें आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पासी चौराहा क्षेत्र का एक प्रमुख मार्ग है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढऩे का खतरा भी बना हुआ है, जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। समाजसेवी अजीत सिंह ने इस गंभीर समस्या को उठाते हुए जिला पंचायत से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने इसे जनसुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए अधिकारियों से शीघ्र संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं पंकज तिवारी, शिवकुमार सिंह, कमला शंकर मिश्रा और शैलेंद्र सरोज सहित अन्य ग्रामीणों ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष व जिलाधिकारी से जल्द समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान न होने पर वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भदोही में महिलाओं की भव्य बाइक रैली, 100 महिलाओं ने लिया हिस्सा

ज्ञानपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 के प्रति आभार और समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से जनपद भदोही में महिलाओं द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिले की लगभग 100 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी एवं ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने हरी झंडी दिखाकर जीआईसी इंटर कॉलेज, ज्ञानपुर से रवाना किया। तिरंगा झंडा हाथों में लिए और 'धन्यवाद मोदी सरकार', 'नारी शक्ति जिंदाबाद' जैसे नारों के साथ महिलाओं ने बुलेट, स्कूटी और बाइक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की। रैली जीआईसी इंटर कॉलेज से शुरू होकर जिला पंचायत कार्यालय पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मनीषा अम्बष्ट ने कहा कि ×× प्रतिशत आरक्षण का यह कानून महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि निणज्य लेने की शक्ति भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी अब सुनिश्चित होगी और यह रैली उसी खुशी और आभार का प्रतीक है। रैली में डॉक्टर, वकील, शिक्षिका, गृहिणी और कॉलेज छात्राओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीषा अम्बष्ट, अर्चना पटेल, सरिता बिंद, पूजा, छाया मौर्य, सुषमा मालवीय, स्नेहलता श्रीवास्तव, रेशमा बानो, लक्ष्मी बिंद, नीलम दुबे, संध्या मौर्य, आराधना शर्मा, सीमा पांडे, महिमा चौधरी, रीना यादव, संजू यादव, अंतिम यादव, रिया यादव, संजू सरोज, निशा बेन, बबीता पांडे, स्वरूप बिंद, आरती सिंह, उर्मिला दुबे समेत बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम ने जिले में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता और उत्साह का संदेश दिया।